

संपादकीय फील गुड से आगे

जिस विशाल बहुमत से नरेंद्र मोदी सत्ता में वापस लौटे हैं, वह अपने आप में इस बात का सबूत है कि आम लोगों में उनके नेतृत्व को लेकर खासा उत्साह है। फिर भी अगर कोई कसर रह गई थी तो मोदी मंत्रिमंडल ने अपनी पहली ही बैठक में कई सकारात्मक फैसले करके उसे पूरा कर दिया। किसान सम्मान निधि योजना से लेकर पेंशन योजना और प्रधानमंत्री छात्रवृत्ति योजना तक में मिलने वाली रकम और इसके दायरे को बढ़ाकर सरकार ने राजकोष पर थोड़ा अतिरिक्त बोझ जरूर डाला है, लेकिन इनके जरिए वह देश में सकारात्मक माहौल बनाने में भी कामयाब रही है।

'मोदी है तो मुमकिन है' नारे के जिस असर को चुनावी माना जा रहा था, वह अब चुनावों के बाद भी कुछ देर तक बना रहेगा, यह तय हो गया है। कई वजहों से राजनीतिक गलियारों में ऐसी चर्चा शुरू हो गई थी कि नतीजे चाहे जो भी आएं, चुनाव के बाद आम लोगों के लिए कठिन दौर शुरू हो जाएगा। ईरान से तेल खरीदने पर रोक के अमेरिकी आग्रह को ध्यान में रखते हुए यह माना जा रहा था कि इस दौर की शुरुआत पेट्रोल-डीजल की कीमतों में तेज बढ़ोतारी से होगी। मगर इस मोर्चे पर अभी तक कोई बड़ी हेतु-फेर नहीं दिखी है। खबर यह भी आई कि भारत सरकार इस मरते पर अमेरिकी आग्रह यूं ही स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

इससे आम लोगों में थोड़ी राहत दिखी, लेकिन रोजगार और जीड़ीपी के आंकड़ों ने स्थितियों की गंभीरता उजागर कर दी। बेरोजगारी दर 45 साल के सबसे ऊंचे स्तर पर और विकास दर पांच साल के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाने की आधिकारिक पुष्टि हो जाने के बाद चिंता के आवेग को थामने का कोई मजबूत आधार नहीं रह गया था। मंत्रिमंडल की पहली बैठक में लिए गए ये फैसले इस आवेग को रोक भले न पाएं, पर इसका असर कम जरूर कर रहे हैं। इससे यह तो होगा कि देश के मीडिया स्पेस में नकारात्मक खबरों का बोलबाला नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन समस्याओं को देखते हुए यह काफी नहीं है। रोजगार और जीड़ीपी ग्रोथ, इन दोनों ही मोर्चों पर जल्दी कुछ करना होगा। दुनिया में ट्रेड वॉर के हालात अलग चिंता का विषय हैं।

ईरान से तेल खरीद पर रोक को लेकर अमेरिका को मनाने की चुनौती तो है ही, डॉनल्ड ट्रंप भारत को व्यापार में तरजीही दर्जा खत्म करने का बाकायदा ऐलान कर चुके हैं, जो इसी हफ्ते पांच तारीख से लागू हो जाएगा। जाहिर है, लोगों की उम्मीद बनाए रखने का काम सरकार के लिए खासा मुश्किल है। आर्थिक सुधार के लिए अंजेंडा पर अमल से शायद कुछ बात बने। उम्मीद करें कि नई पारी में मोदी सरकार अपनी प्राथमिकताएं पहले से ज्यादा स्पष्ट रखेगी।

पिज्जा सॉस बनाने की विधि...

पिज्जा सभी को पसंद होता है लेकिन इसका टेस्ट पिज्जा सॉस के साथ ही मजेदार लगता है। आज जगह जगह



कैचअप- 1/2 कप, टमैटो प्यूरी- 2 कप, नमक-1 टेबलस्पून, लाल मिर्च पाउडर-2 टेबलस्पून, मिश्रित जड़ी बूटियां-2 टेबलस्पून

विधि

पहले आप एक पैन को गर्म करें तथा उसमें 2 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल को डालें। अब आप उसमें कटी लहसुन की कलियां डाल कर उनको आधा मिनट तक फ्राई करें। इसके बाद आप इसमें टमैटो प्यूरी डालकर उस समय तक चलाते रहें जब तक टमाटर का रस भाप बनकर न उड़ जाए। इसके बाद आप इसमें नमक तथा लाल मिर्च को भी डालें। इसके बाद आप इसमें मिश्रित जड़ी बूटियां, कैचप और टमाटर की चटनी डालें। अब आप इसको कुछ देर अच्छे से चलाएं तथा गैस को बंद कर दें। इस प्रकार से आपकी पिज्जा सॉस आसानी से बन जाती है।

सामग्री

प्याज-1 (बारीक कटी हुई), लहसुन- 5 से 6 (कटे हुए), टमैटो

पीएम किसान से 8 लाख अमीर किसानों को भी मिलेगा फायदा, भूमिहीन अब भी वर्चित

नई दिल्ली। पीएम नरेंद्र मोदी ने दूसरे कार्यकाल की पहली कैबिनेट बैठक में ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (पीएम-किसान) का दायरा बढ़ाने पर मुहर लगा दी। सरकार के इस फैसले से देशभर के 8 लाख ऐसे अमीर किसानों को भी फायदा मिलेगा, जिनके पास 10 हेक्टेयर (करीब 25 एकड़) या इससे अधिक जमीन है।

हालांकि, भारत में कुल किसानों में इनकी हिस्सेदारी मजबूत 0.6 फीसदी ही है। सबसे अधिक जमींदार किसान राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पंजाब, कर्नाटक, हरियाणा और गुजरात में हैं। राजस्थान के विशेषण से पता चलता है कि पंजाब के कुल किसानों में 5.3 फीसदी इस श्रेणी में आते हैं। इनी तरह राजस्थान में 4.7 फीसदी और हरियाणा में 2.5 फीसदी बढ़े किसान हैं। दूसरे राज्यों में ऐसे किसानों की संख्या 1 फीसदी से कम है।



भूमि की उर्तरा शक्ति, सिंचारा बड़े किसान से एक संख्या है। दूसरे तरफ के साधन आदि को ध्यान में रखकर उत्पादकता की बात करें तो राजस्थान की तुलना पंजाब और हरियाणा में 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में बड़े किसानों की संख्या ना के बराबर है। तेलंगाना में 9 हजार बड़े किसान हैं तो असम और ओडिशा में 4-4 हजार।

बिहार और हिमाचल में इनकी संख्या 3-3 हजार है। केरल में 2 हजार और उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल और जम्मू-कश्मीर में 1-1 हजार किसानों के पास 25 एकड़ या इससे अधिक भूमि है। ये अंकड़े एप्रिल-मेसेस 2015-16 से लिए गए हैं, जो पीएम किसान योजना के लिए डेटाबेस के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है।

विस्तार देते हुए अधिकतम 2 हेक्टेयर भूमि की सीमा हटा दी। इसके बाद देश के सभी 14.5 करोड़ किसान इस योजना के दायरे में आ गए हैं।

इस योजना के तहत सभी किसानों को 6000 रुपये सालाना आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है, 2-2 हजार रुपये की तीन किश्तों में यह राशि दी जाती है। हालांकि, इस योजना का लाभ भूमिहीन किसानों को नहीं मिल पाएगा। योजना के विस्तार से 2 करोड़ अतिरिक्त किसानों को लाभ मिलेगा, जिसमें 8 लाख बड़े किसान शामिल हैं।

भूमिहीन को फायदा नहीं

केंद्र सरकार ने शुक्रवार को पीएम किसान योजना को

पेट्रोल के भाव 7 पैसे लीटर घटे, डीजल हुआ 20-22 पैसे सस्ता

नई दिल्ली (आरएनएस)। सूक्ष्म वित्त डिव्यू का सकल ऋण प्रतीकालीयों मार्च, 2019 के अंत तक बढ़कर 1,87,386 करोड़ रुपये पर पहुंच गया। सालाना आधार पर यह 38 प्रतिशत की वृद्धि है। माइक्रोफाइनेंस इस्टिट्यूशन्स नेटवर्क (एमएफआईएन) की सोमवार को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार मार्च, 2019 तक कुल सूक्ष्म वित्त स्थानों की कीमतों में तेज बढ़ोतारी से होगी। मगर इस मोर्चे पर अभी तक कोई बड़ी हेतु-फेर नहीं दिखी है। खबर यह भी आई कि भारत सरकार इस मरते पर अमेरिकी आग्रह यूं ही स्वीकार करने के मूड में नहीं है।

इंडियन ऑयल की वेबसाइट के अनुसार, दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम अनुप्राप्त रूप से प्रति लीटर की कटौती की, जबकि डीजल के दाम भिन्न भिन्न रूप से प्रति लीटर की कटौती की। डीजल के दाम भी चारों में महानगरों में घटकर ऋणश: 65.56 रुपये, 67.48 रुपये, 68.76 रुपये और 69.36 रुपये प्रति लीटर हो गए हैं।

तेल विपणन कंपनियों ने मंगलवार को दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई में पेट्रोल के दाम में सात पैसे प्रति लीटर की कटौती की, जबकि डीजल के दाम भिन्न भिन्न रूप से प्रति लीटर हो गए हैं। डीजल के दाम भी चारों में महानगरों में 20 पैसे, मुंबई में 21 पैसे और चेन्नई में 22 पैसे लीटर हो गए हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे गिरावट के दाम में लगातार सातवें दिन तेल के दाम में कमी आई है। डीजल के दाम में कमी आएगी। इस



दैरान बैंचमार्क कच्चा तेल ब्रॉन्ट कर्लूड के दाम में लगभग 10 डॉलर प्रति लीटर की कमी आई है। उर्जा विशेषज्ञ ने देंद्र तेजों का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे गिरावट के बाद भारत में पेट्रोल और डीजल के दाम में कमी आएगी। इस अपभूक्तों को राहत मिलेगी।

आखीआई ने दी एक्सिस बैंक के चेयरमैन पद पर

राकेश मर्खीजा की नियुक्ति को मंजूरी

नई दिल्ली (आरएनएस)। निजी क्षेत्र के एक्सिस बैंक ने सोमवार को कहा कि रिजर्ज बैंक

ने बैंक के चेयरमैन पद पर परियोजनाओं को आगे बढ़ाया और ढांचागत विकास के क्षेत्र में काफी काम किया। गडकरी ने दोनों मंत्रालयों की कार्यभार सभाताने के मौके पर कहा, 'प्रधानमंत्री ने गडकरी के पद पर मर्खीजा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक के बोर्ड ने मार्च में चेयरमैन के पद पर मर्खीजा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। बैंक के बोर्ड ने मार्च में चेयरमैन के पद पर मर्खीजा की नियुक्ति को मंजूरी दी है। उनकी नियुक्ति 18 जुलाई, 2019 से 17 जुलाई, 2022 तक के लिए प्रभावी है। मर्खीजा ने अपने पहले मैच से प